जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

उदयपुर

Rashtradoot

फोनः- 2418945 फैक्सः- 0294-2410146 वर्षः 30 संख्याः 106 प्रभात उदयपुर, गुरुवार 16 फरवरी, 2023 आर.जे. 7202 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

कुछ वानर अपना सारा जीवन वृक्षों पर गुज़ार देते हैं और प्रायः जमीन पर नहीं आते, क्योंकि यहां उनका पसंदीदा भोजन कम मिलता है और परभक्षी जीवों का खतरा भी ज्यादा होता है। पर वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन से इनके प्राकृतिक आवास खतरे में पड़ रहे हैं। इस वजह से कुछ वानर भोजन की तलाश में जमीन पर आने लगे हैं। प्रोसीडिंग्स ऑफ नैशनल अकैडमी ऑफ साईन्सेज़ में छपे एक शोध में वैज्ञानिकों ने यह जानकारी दी है। दुनियाभर के 118 शोधकर्ताओं ने 34 साल तक मैंडागास्कर तथा अमेरिका में लीमर और पेड़ों पर रहने वाले वानरों का अध्ययन किया। कैलिफोर्निया में सैन डिएगो ज़ू वाइल्डलाइफ अलायन्स के टिमथी एपली, जो शोध के सहलेखक भी हैं, ने कहा, हम यह समझना चाहते थे कि, किन कारणों की वजह से वानर जमीन पर ज्यादा नजर आने लगे हैं। सहलेखक पैट्रीशिया राइट ने कहा, जिन वानरों का अध्ययन किया गया था, उन्होंने औसतन 5 प्रतिशत से भी कम समय जमीन पर गुजारा, हालांकि यह ज्यादा नहीं है, पर जमीन पर एक सैकेंड का समय भी भारी पड़ सकता है, खासकर परभक्षी को देखते हुए। इसके बावजूद कुछ वानर जमीन पर उतरने का खतरा उठा रहे हैं। शोध में यह भी पता चला कि, अलग-अलग प्रकार का भोजन करने वाले और बड़े समूहों में रहने वाले वानर जमीन पर रहने की स्थिति से आसानी से अनुकूलन कर सकते हैं। छोटे आकार के वानर भी ऐसा कर सकते हैं, जो कि एक अप्रत्याशित निष्कर्ष है। वैज्ञानिक अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है। प्राइमेट एक्सपर्ट, स्टोनी ब्रूक युनिवर्सिटी के जॉन फ्लीगल, जो हालांकि शोध का हिस्सा नहीं थे, का कहना है कि इन नतीजों से पता चलता है कि, हालांकि वानरों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं पर कुछ वानर ऐसे नए आवास से डील कर सकते हैं, जो उनके मूल प्राकृतिक आवास से नीचे हैं। एक निराशाजनक निष्कर्ष यह है कि, इमारतों और सड़क के आसपास रहने वाले वानर नीचे नहीं उतरते। संरक्षणविद इनकी मदद के लिए रणनीति बना रहे हैं, जैसे प्राकृतिक आवासों को परस्पर जोड़ने के लिए रोप ब्रिज का निर्माण आदि। इस शोध में जिन प्रजातियों का अध्ययन किया गया, उनमें प्रमुख हैं, ब्राज़ील के ब्राउन हाउलर्स (जो चित्र में नज़र आ रहे हैं), हमबोल्ट के वूली मंकी, वाइटफेस्ड कापुचिन, मैंडागास्कर में वेरो सिफाका, सदर्न बैम्बू लीमर और रिंग टेल्ड लीमर आदि।

रायपुर अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी अपने संविधान में संशोधन करेगी?

प्रमुख संशोधन होगा कि, पूर्व पार्टी अध्यक्ष जीवन पर्यन्त सी.डब्ल्यु.सी. के सदस्य होंगे

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15 फरवरी। ऐसे पक्के संकेत हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने संविधान में संशोधन कर सकती है तथा पूर्व कांग्रेस अध्यक्षों को कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सी.डब्ल्यु.सी.) का आजीवन सदस्य बना सकती है। ज्ञातव्य है कि सी.डब्ल्यु.सी. कांग्रेस पार्टी की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च समिति है।

सूत्रों ने कहा कि इस संशोधन का उद्देश्य सोनिया गांधी तथा राहुल गांधी को सी.डब्ल्यु.सी. का आजीवन सदस्य बनाने का है। चूँकि अन्य कोई पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष जीवित नहीं है, इसलिये इस समय तो यही अपेक्षा है कि यह संशोधन इन्हीं दोनों पर लागू होगा।

बाद में, अगर और जब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष पद से मुक्त हो जायेंगे तो वे भी इसी कोटि में शामिल हो जायेंगे।

वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी, जो गांधी परिवार के नज़दीक मानी जाती हैं, संविधान संशोधन समिति की अध्यक्ष बनाई जा चुकी हैं जिसके द्वारा 24 से 26 फरवरी तक रायपुर में होने वाले पार्टी महाधिवेशन में यह संविधान-संशोधन पेश किया जा सकता है।

चुनाव समिति के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि जहाँ तक सी.डब्ल्यु.सी. के चुनावों का प्रश्न है, चुनाव अधिकारी पूरी तरह तैयार हैं तथा 24 घंटे के नोटिस पर चुनाव कराये जा सकते हैं।

- **फिलहाल दो ही पूर्व कांग्रेसाध्यक्ष जीवित हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी इस संशोधन का लाभ मिलेगा, जब वे पद छोड़ेंगे।**
- **अंबिका सोनी को संविधान संशोधन समिति का अध्यक्ष बनाया है तथा वे पार्टी हाई कमान की अति विश्वासी व नजदीक मानी जाती हैं।**
- **इस बार ए.आई.सी.सी. के सदस्यों की चयन प्रक्रिया की बहुत सख्ती से अनुपालना होने की भी चर्चा है। पार्टी के संविधान के अनुसार आठ पी.सी.सी. सदस्यों पर एक ए.आई.सी.सी. सदस्य बनेगा।**
- **सोनिया गांधी के समय ज्यादा से ज्यादा ए.आई.सी.सी. के सदस्य बनाये जाते थे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग अधिवेशन में भाग ले सकें।**
- **इस बार अधिवेशन में भाग लेने वालों की संख्या कानून की प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित की जाएगी और भीड़ इकट्ठी नहीं की जाएगी तथा निर्वाचित सदस्यों को ही बुलाया जाएगा।**

ए.आई.सी.सी. सदस्यों की सूचियाँ तैयार हो रही हैं तथा पार्टी पी.सी.सी. के हर 8 सदस्यों के लिये 1 ए.आई.सी.सी. सदस्य के निर्धारित मानक का पूरी तरह ध्यान रख रही है।

इससे पहले, जब सोनिया गांधी के कार्यकाल में सी.डब्ल्यु.सी. के लिये चुनाव नहीं कराये जा रहे थे, पार्टी के बहुत सारे सदस्य ए.आई.सी.सी. के सदस्य बना दिये गये थे ताकि वे अधिवेशन में शामिल हो सकें। लेकिन इस समय चल रही छँटाई के चलते, मूल संख्या का पूरा ध्यान रखा जा रहा है।

एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिये किया जा रहा है कि संविधान के नियमों का पूरी तरह पालन हो सके, जिससे कोई सदय सी.डब्ल्यु.सी. चुनावों की प्रक्रिया को चुनौती नहीं दे सके।

कांग्रेस तथा दिल्ली के मीडिया में इस बिंदु पर गहन अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर सी.डब्ल्यु.सी. के चुनाव होते हैं तो क्या सचिन पायलट इसके लिये चुनाव लड़ेंगे।

बी.बी.सी. कार्यालयों पर आई.टी. सर्वे दूसरे दिन भी जारी रहा

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15 फरवरी। बी.बी.सी. इंडिया के खिलाफ आयकर विभाग की जाँच आज दूसरे दिन भी जारी रही तथा बताया जाता है कि अधिकारियों ने कंपनी के इलैक्ट्रॉनिक तथा कागज़ -आधारित वित्तीय डेटा की कॉपी की।

- **सूत्रों ने बताया कि, बी.बी.सी. इंडिया के वित्तीय दस्तावेजों की कॉपी करने का साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों के फोन की क्लोनिंग भी की।**

ज्ञातव्य है कि आई.टी. के इस सर्वे से चन्द सप्ताह पहले ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा 2002 के गुजरात दंगों

(शेष पृष्ठ 5 पर)

"फिच" पाकिस्तान रेटिंग, सी.सी.सी.+ से सी.सी.सी.- हो गयी

अन्तर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ने यह भी कहा कि, तीन सप्ताह में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा का रिज़र्व 20 अरब डॉलर से घट कर 2.9 अरब डॉलर ही रह गया है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15 फरवरी। पाकिस्तान के मित्र माने जाने वाले देशों और वैश्विक सामरिक सलाहकारों ने उसे सलाह दी है कि वह अपनी आत्मसंतुष्टि की प्रवृत्ति त्यागे, कश्मीर को भूल जाए और भारत से दोस्ती करे। अब समय अर्थव्यवस्था की मजबूती पर फोकस करने का है जो दशकों तक अनदेखी किए जाने की पीड़ा भुगत रही है।

पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी "फिच" ने भी अब इस वास्तविकता की पुष्टि कर दी है। उसने पाकिस्तान की दीर्घकालिक फॉरेन करेंसी इश्यूअर डिफाल्ट रेटिंग (आई.डी.आर.) को सी.सी.सी. प्लस से कम करके सी.सी.सी. माइनस" कर दिया है।

- **पाकिस्तान के पुराने मित्रों ने, चीन, सऊदी अरब व यू.ए.ई. ने भी हाथ खींच लिया।**
- **इन देशों का कहना है, पाकिस्तान आतंकवादी गिरोहों को फायनैंस करना बंद करे, क्योंकि इससे विदेश से आने वाला "फॉरैन डायरैक्ट इन्वैस्टमैंट" सूख गया है तथा चीन पर अति निर्भरता भी गलत नीति साबित हुई है।**

यह अवनति बाह्य तरलता और फण्डिंग कंडीशन्स में आई तीव्र कमी को दर्शाती है और फॉरैन एक्सचेंज रिज़र्वज़ के एकदम नीचे के स्तरों के बारे में इंगित करती है। फिच ने कहा कि रेटिंग का कमजोर पड़ना यह भी दर्शाता है कि पाकिस्तान में इस वर्ष होने वाले आम चुनावों से पूर्व सरकारी योजनाओं को जारी रखने और फण्डिंग को लेकर बड़ी जोखिमपूर्ण स्थिति है। चूक अथवा ऋण

(शेष पृष्ठ 5 पर)

मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ ने बजट की प्रतियां जलाईं

जयपुर, 15 फरवरी (का.प्र.)। राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ ने बजट घोषणा 2023-2024 में मंत्रालयिक कर्मचारियों की अनदेखी को लेकर प्रदेश भर के 33 जिलों में जिला कलैक्टर कार्यालयों में एवं 360 ब्लॉकों में उपखंड मुख्यालयों पर बजट के कर्मचारी कल्याण के चैप्टर की प्रतियों की होली जलाई और सम्पूर्ण प्रदेश में कार्य बहिष्कार कर विरोध दर्ज कराया। जयपुर में जिला कलैक्टर कार्यालय पर जयपुर के सभी विभागों

- **राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ ने मंत्रालयिक कर्मचारियों की उपेक्षा के प्रति विरोध जताते हुए राज्यभर में जिला कलैक्टर कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया।**

(शेष पृष्ठ 5 पर)

अब आसाम व महाराष्ट्र में घमासान छिड़ा?

कांग्रेस, भाजपा आदि विपक्ष का आरोप है, "एकनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा महाराष्ट्र में लगने वाले उद्योगों की रक्षा नहीं कर पाना और अब महाराष्ट्र की सांस्कृतिक व धार्मिक धरोहर को भी लुटने देना"

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15 फरवरी। धर्म और राजनीति के घालमेल से एक बार फिर एक विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल, भाजपा शासित असम सरकार ने एक विज्ञापन जारी किया है जिसमें दावा किया गया है कि छठा ज्योतिर्लिंग इस पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है, जबकि केन्द्र सरकार के 2021 के एक सर्कुलर के अनुसार, छठा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले के भीमाशंकर में है।

महाराष्ट्र में विपक्ष के नेताओं, जिनमें शिवसेना, यू.बी.टी., कांग्रेस

- **इस मुद्दे ने जोर पकड़ा, जब, आसाम सरकार ने बड़े-बड़े विज्ञापन छपवाकर दावा किया कि, छठा ज्योतिर्लिंग आसाम में है।**
- **अब तक महाराष्ट्र में यह माना जाता था कि, छठा ज्योतिर्लिंग, भीमशंकर, महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है।**
- **इस विज्ञापन से महाराष्ट्र शिव सेना-भाजपा की सरकार रक्षात्मक मुद्रा में आ गयी है। भाजपा के महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य, विधायक राम कदम ने कुछ लीपा पोती की कि, विपक्ष नाहक ही फिज़ूल का मुद्दा बना रहा है, क्योंकि सभी जानते हैं भीमशंकर महाराष्ट्र में है।**

(शेष पृष्ठ 5 पर)

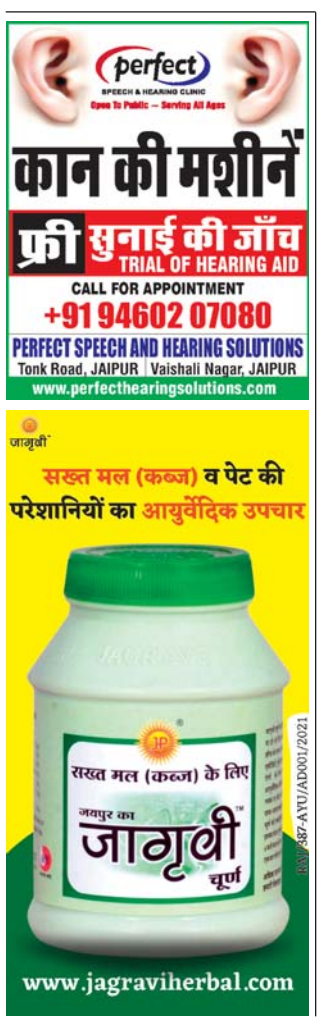

'भूमिगत पानी का स्तर, खतरे के निशान के नीचे पहुंचा'

जाते-जाते सरकार को इस संकट का आभास हुआ?

- **केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट तक, राज्य सरकार को साल भर पहले प्राप्त हो गयी थी।**
- **रिपोर्ट में साफ लिखा है, राज्य के सभी 33 में से 31 जिलों में भूमिगत पानी का एक्स्प्लॉयटेशन 151 प्रतिशत तक है, यानि, जितना पानी का भराव होता है भूमिगत स्रोत में, उससे ज्यादा पानी बड़े-बड़े पम्पों द्वारा निकाल लिया जाता है।**
- **सदन के उप नेता ने यह मुद्दा विधानसभा में उठाया, तो पी.एच.ई.डी. मंत्री ने भयावह स्थिति स्वीकार की और कहा, शीघ्र ही राज्य सरकार स्थिति पर नियंत्रण पा लेगी, क्योंकि तीन दिन पहले ही उन्होंने फाइल पर हस्ताक्षर किये हैं।**

जयपुर, 15 फरवरी (वि.सं.)। राजस्थान सूखा प्रदेश है, जहां जनसंख्या बढ़ने और औद्योगिककरण होने से भूजल दोहन की समस्या कई दशकों से चली आ रही है। हद तो तब हुई जब केंद्र सरकार ने गत वर्ष 33 जिलों का सर्वे कर भूजल के 'ओवर एक्सप्लॉयटेशन' की जानकारी दी फिर भी राज्य सरकार ने इसे रोकने के संरक्षण के संबंध में कोई कदम नहीं उठाया।

आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने भूजल दोहन का मामला उठाया। उन्होंने दशकों से चली आ रही इस समस्या के संदर्भ में नये तथ्य प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रदेश में भूजल संरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा गठित भूजल संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण का गठन तो दूर अब तक उसका प्रारूप भी तैयार नहीं हो पाया है। उन्होंने केंद्र सरकार के जल मंत्रालय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में भूजल की खपत 151 प्रतिशत की दर से हो रही है, यानी भूजल जितना एकत्रित हो रहा है उससे ज्यादा दोहन हो रहा है, परंतु अभी तक प्रदेश में भूजल संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण का गठन क्यों नहीं किया गया है और जल्द से जल्द होना चाहिए।

इस पर भू-जल मंत्री डॉ. महेश जोशी ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि राज्य में भू-जल दोहन के नियन्त्रण के लिए राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही राज्य भू-जल संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। महेश जोशी ने सदन को बताया कि भूजल संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के गठन को प्रस्तावित करने वाली फाइल को तीन दिन पहले ही स्वीकृति दी गई है और राज्य सरकार शीघ्र ही इसे अमल में लाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य स्तर पर इस संबंध में प्राधिकरण बनाने के लिये ड्राफ्ट विधि विभाग तथा वित्त विभाग को भेजा गया था, हाल ही में उनकी आपत्तियों का निस्तारण किया गया है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के जल संसाधन मंत्रालय ने 3 मार्च को ग्राउंड लैवल का सर्वे किया था जिसके तहत पाया गया था कि प्रदेश के 33 जिलों में 295 ब्लॉक में से 219 ब्लॉक्स में भूजल स्तर 'ओवर एक्सप्लॉयटेशन' श्रेणी में आता है, 22 ब्लॉक्स संवेदनलशील श्रेणी में आते हैं, 20 ब्लॉक्स अर्द्धसंवेदनशील श्रेणी में और केवल 38 ब्लॉक ही सुरक्षित श्रेणी में आते हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि 'ओवर एक्सप्लॉयटेशन' श्रेणी में प्रदेश के सभी बड़े शहर और जिले शामिल हैं जिनमें जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, अजमेर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर शामिल हैं। केवल गंगानगर, हनुमानगढ़ और डूंगरपुर ही ऐसे जिले हैं जो सुरक्षित श्रेणी में आते हैं।

सदन में जवाब के दौरान मंत्री महेश जोशी ने माना कि केंद्र सरकार की यही मंशा रही है कि राज्य सरकार अपने स्तर पर ही भूजल संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कर ले और भूजल संरक्षण की नीति लागू करने का जिम्मा स्वयं ही उठाये, परंतु इस सरकार के पांचवे वर्ष में भी इस प्राधिकरण का गठन नहीं हो पाया हैं।

सदन में जब महेश जोशी जवाब दे रहे थे उसी दौरान उप नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने उनसे पूछा कि प्रदेश में केवल कृषि उपयोग और घरेलू उपयोग के लिये भूजल के उपयोग पर कोई प्रभार लागू नहीं है, परंतु वह बतायें कि जयपुर, बीकानेर, कोटा, भीलवाड़ा और अजमेर जैसे बड़े शहर जहां भूजल स्तर 'ओवर एक्सप्लॉयटेशन' श्रेणी में है, वहां राज्य सरकार ने कंपनियों द्वारा भूजल का उपयोग करने के लिये उनसे क्या हर्जाना लिया है? इस पर डॉ. महेश जोशी ने कहा कि वे केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार ही काम रहे हैं परंतु उनके पास उनको बताने के लिये कोई आंकड़े तैयार नहीं हैं।

ब्लड बैंक से कुत्ते ले गये खून के सैंपल

जयपुर, 15 फरवरी (वि.सं.)। विधानसभा में आज शून्यकाल के दौरान ब्लड बैंक से कुत्तों द्वारा सैंपल उठा ले जाने का मामला गूंजा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने शून्यकाल में यह मामला उठाते हुए बताया कि 11 फरवरी को ब्लड बैंक से कुत्ते मरीजों के खून के सैंपल उठाकर ले गए।

राठौड़ ने कहा कि यूपी की टास्क फोर्स ने लखनऊ से ब्लड की तीन हजार

- **विधानसभा में शून्यकाल के दौरान उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने यह मुद्दा उठाया।**

थैलियां पकड़ी, जिनमें सैलाइन वाटर डालकर मात्रा दोगुनी की गई थी। यूपी एसटीएफ ने राजस्थान के ड्रग कंट्रोलर को सूचित किया था कि इन पर राजस्थान का मार्क है। यूपी एसटीएफ से इनपुट मिलने के बावजूद सरकार ने कार्रवाई नहीं की। राजस्थान में शराब तस्करी की तर्ज पर ब्लड तस्करी शुरू हो चुकी है। सरकार को ब्लड तस्करी की जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करना चाहिए।